



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

**सा.का.नि. 145(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 17 के साथ पठित धारा 53 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 17 और 18 तथा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधियों का निपटान (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- माल और सेवा कर निधियों का निपटान नियम, 2017 के नियम 11 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) केन्द्रीय सरकार, किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में किसी भी समय, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष में संग्रहीत एकीकृत माल और सेवा कर की किसी राशि का अनंतिम रूप से निपटान कर सकेगी जिसका अब तक निपटान नहीं किया गया है।”

[फा. सं. एस-31013/16/2017-एसटी-I--डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 964(अ), तारीख 27 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2018

**G.S.R. 145(E).**—In exercise of the powers conferred by section 53 read with section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), sections 17 and 18 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendments in the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Settlement of Funds (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017, in rule 11, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) At any point of time in any particular financial year, the Central Government may, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, provisionally settle any sum of integrated goods and services tax collected in that particular financial year which has not been settled so far.”

[F. No. 31013/16/2017-ST-I-DoR]

S. R. MEENA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 964(E), dated the 27th July, 2017.